

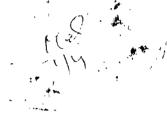
## **EXTRAORDINARY**

भाग II---खाण्ड 3 --- उप-खाण्ड ( I )

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं• 37 ] No. 371 नई विस्ती, बुधवार, फरवरी 4, 1998/माप 15, 1919 NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 4, 1998/MAGHA 15, 1919

महानिदेशक (रक्षोपाय)

# अधिसूष्रमा

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1998

विषय : -- एसिटिलिन ब्लैक (ए बी) के आयात से संबंधित रक्षोपाय जॉब का प्रारम्भिक निष्कर्ण।

सा.का.नि. 68 (अ).— एस जी/आई एन बी/1/97 दिशांक 27 जनवरी, 1998—सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 और सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय) शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियमावली, 1997 को ध्यान में रखते हुए।

#### 1. प्रक्रिया

एसिटिलिन ब्लैक (ए बी) के भारत में आयात से संबंधित रक्षोपाय जाँच शुरू करने के लिए दिनांक 28-11-97 को नीटिस जारी किया गया था और उसी दिन इसे भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। नीटिस की एक प्रति निम्नलिखित सभी ज्ञात इच्छुक पक्षों को भेजी गई थी:— बरेलू उत्पादक

- मैसर्स टेसिल केमिकल्स एण्ड हाइड्रो पांचर लिमिटेड, मुम्बई-400001
- मैसर्स पन्यम सीमेंट्स एण्ड मिनरल्स इण्डस्ट्रीज शिमिटेड, हैदराबाद-500029
- मैसर्स सेन्का कार्बन प्राइवेट लिमिटेड, चैन्नई-600090
- मैसर्स ओसवाल पैट्रो केमिकल्स, मुम्बई-400074

## आयातकर्ता

- मैसर्स एकरेडी इण्डस्ट्रीज इण्डिया लिमिटेड, कलकता-700019
- मैसर्स इन्डो नेशनल लिमिटेड चैन्नई-600034

317 GI/98

- मैसर्स लखनपाल नेशनल लिमिटेड. बडौदा-390010
- मैसर्स जीप इण्डस्टीज सिंडीकेट लिमिटेड. इलाहोबाद ।

#### निर्पातक

- मैसर्स डेन्की कागाक कोग्यो काब्शिकी कैशा (डेंका), जापान।
- मैसर्स डेंकी कागाक कोग्यो काबुशिकी कैशा (डेंका) (डी एस पी एल), सिंगापर।
- मैसर्स कार्बोंकेम. साऊथ अफ्रीका
- दि सोसायटी डू नोयर, डी एसिटिलिन,
- मै. मात्सुशीता इलेक्ट्रानिक इण्डिस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेड. जापान-चाईनीज निर्यातक के एजेंट।
- मै. एम सी सी आई कारपोरेशन, फिलिपिन्स
- मैसर्स एक. एम. एम. एस. ए.. बेल्जियम

निर्यातक देशों की सरकारों को भी दिल्ली स्थित उनके दूतावासों के माध्यम से नोटिस की एक प्रति भेजी गई थी। सभी जात घरेल उत्पादकों और आयातकों को उसी दिन प्रश्नावली भी भेजी गई थी और उनसे 37 दिन के अन्दर अपना जवाब भेजने के

लिए कहा गया था। अपने जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा बढ़ाने के लिए निम्नलिखित पर्श्वो द्वारा अनुरोध किया गया था।

- 1. मैसर्स डेन्की कागाक कोग्यो काब्शिकी कैशा, जापान।
- 2. इडी एस पी एल, सिंगापुर
- 3. मैसर्स एम. एम. एम. एस. ए., बेल्जियम
- मैसर्स कार्बोकेम, साऊथ अफ्रीका
- 5. दि सोसायटी इ नोयर, डी एसिटिलिन, फ्रांस
- ऊपर लिखे नाम के सभी चारों आयातक।

उनकी प्रार्थना और सांविधिक समय सीमा में जांच पुरी करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 19 जनवरी, 1998 तक के लिए समय सीमा के विस्तार की अनुमति दी गई थी तथा तदनुसार संबंधित पक्षों को सूचित कर दिया गया था। दि केमिकल्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आफ इण्डिया, चैन्नई ने एक इच्छुक पार्टी के रूप में समझे जाने के लिए आवेदन किया था जिसे मान लिया गया था।

तीन घरेल उत्पादकों यथा मै. टेसिल, मै. पन्यम और मै. सेन्का उपरोक्त नामित सभी चारों आयातक और निर्यातक यथा कागाक कोग्यो केशा, डी एस पी एल, एम. एम. एम. एस. ए., कार्बोंकेम और सोसायटी इ नोयर से दिनांक 28-11-97 के नोटिस और प्रश्नावली के जवाब प्राप्त हुए हैं।

एसोसिएशन आप ड्राइसेल बैटरीज मैन्युफैक्बरर्स (एडीसीबीएम) की तरफ से दिनांक 28-11-97 के नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया है। एडीसीबीएम का नाम न तो घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन में है और न ही एडीसीबीएम ने दिनांक 28~11-97 के नोटिस के पैराग्राफ 10 के अनुसार इच्छुक पक्ष समझे जाने के लिए कोई अनुरोध किया है। उपरोक्त बातों के रहते हुए भी एडीसीबीएम द्वारा प्रस्तुत जवाब में उठाए गए सुद्दीं पर उचित स्थान पर विचार किया गया है।

# 2. घरेल उद्योगों का दुष्टिकोण

घरेलु उत्पादकों ने निम्नलिखित मुख्य मुद्दे उठाए हैं :--

- (क) उनका उत्पाद एसीटिलिन ब्लैक (एबी) कार्बन ब्लैक की एक उच्च किस्म थी और 1987 के आई एस 12178 के अनुसार है, एवं जापानी विनिर्देश जे. आई. एस. 1469-1984 एवं दूसरे अंतर्राष्ट्रीय विनिर्देशों की तुलना के योग्य एवं न्यूनाधिक उन्हीं जैसी है।
- (ख) एबी मुख्यतः ड्राइ सेल बैटरी के विनिर्माण में काम आती है और उसके ग्राहक ड्राइसेल बैटरी के विनिर्माता थे।
- (ম) 90% से ज्यादा एबी को कैल्सियम कार्बाइड विधि द्वारा बनाते थे। कार्बाइड में जिसे मुख्य वस्तु की आवश्यकता थी वह थी विद्युत जो कि 1988-89 में 0.95 पैसे प्रति युनिट से बढ़कर वर्तमान में 2.85 रुपये प्रति युनिट हो गयी है इसलिए एबी के उत्पादन की लागत बढ़ रही थी।

- (घ) वे वर्ष 1995-96 तक ड्राई सैल बैटरी के निर्माताओं की मांग पूरी कर रहे थे और वास्तव में एबी का थोड़ा सा आयात हुआ। वर्ष 1996-97 में एबी के आयात में एकाएक वृद्धि शुरू हुई और उनके ग्राहकों ने उनसे एबी की कुल खरीद में कमी कर दी।
- (क) एबी का सी आई एफ आयात मूल्य अक्तूबर, 1996 में यू एस डी 2500/-मी. ट. से 1997-98 में यूएसडी 1700 मी. टन तक गिर गया और आयात मूल्य में और भी गिरावट आने के संकेत हैं।
- (च) सभी ड्राईसैल विनिर्माताओं ने उनसे लगातार सम्पर्क करके यह कहकर एबी के मूल्य कम करने के लिए कहा कि जापान, साउथ अफ्रीका और फिलीपिन्स तथा अन्य देशों से एबी सस्ते मूल्य पर मिल रहा था। वास्तव में उन्होंने केवल कीमतों को ध्यान में रखकर घरेलू निर्माताओं से एबी की कुल खरीद कम करने की धमकी दी।
- (छ) मै. इन्डों नेशनल लिमिटिड ने मै. सेंका को 1992 में एक प्रमाण-पत्र जारी किया कि वे उनकी गुणवता, मात्रा और तुरन्त सेवा से संतुष्ट थे।

# । 3. निर्यातकों ∕निर्यातक देशों की सरकारों के दृष्टिकोण :—

भारत में एबी के निर्याताकों ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किए हैं।

- (क) सोसायटी इ नोयर डी एसीटिलिन फ्रांस।
  - (i) कि वे 1980—85 में भारत में उच्च सीमा शुल्क होने के बावजूद एबी का निर्यात कर रहे क्योंकि उस समय भारतीय बाजार की आवश्यकता पूर्ति के लिए घरेलू उत्पादन काफी नहीं थे।
  - (ii) 1987-88 में उन्होंने एखी का निर्यात कम निर्यात मूल और एखी के घरेलू उत्पादन के स्तर के कारण बंद कर दिया था।
  - (iii) 1996 में उन्होंने एबी का भारत में निर्यात इसिलए किया क्योंकि घरेलू निर्माता उत्पादन समस्या (बिजली की कमी) का सामना कर रहें थे और 1996 के आखिर में उन्होंने इसिलए निर्यात बंद कर दिया क्योंकि उस समय भारी मूल्य प्रतियोगिता चल रही थी।
- (ख) डेंकी कागाकू कोग्यो का बृशिकी कैश (डेंका)
  - (i) डेंका जापान एबी का निर्माण कैल्सियम कार्बाइड विधि द्वारा और डीएसपीएल सिंगापुर पेट्रोकेमिकल्स के जरिए निर्माण करते हैं।
  - (ii) आयात में भी कोई बढ़ोतरी नहीं थी और न ही मूल्यों में कमी थी जिससे कि घरेलू उत्पादकों को कोई क्षति पहुंचे।
  - (iii) भारत में आयात मूल्य अंतराष्ट्रीय बिक्री मूल्य के अनुसार था और विशेष रूप से अंतराष्ट्रीय मानकों की तुलना में कम नहीं था।
  - (iv) मरेलू उत्पादन में गिरावट ज्यादा नहीं थी। गिरावट के कारण वर्धित निर्यात के अलावा अन्य भी हो सकते हैं।
- (ग) जपानी दूतावास नई दिल्ली में उल्लेख किया है कि वह आने वाले समय में आवश्यक टिप्पणी भेजेगा।

## आयातकों के दृष्टिकोणः—

एबी के घरेलू उपभोक्तओं जो कि एबी के आयातक भी हैं, ने निम्नलिखित दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं:--

- (क) मै. जीय इंडस्ट्रीयल सिंडीकेट लिमिटिड ने अपने विचार निम्न प्रकार व्यक्त किए हैं।
  - (i) वे ड्राई सेल बैटरियों का निर्माण करते हैं और एबी को कच्चे माल की तरह प्रयोग करते हैं।
  - (ii) मार्च, 96 तक उनकी पूरी मांगे घरेलू सप्लायरों द्वारा पूरी की जा रही थी।
  - (iii) उन्होंने वर्ष, 96 से घरेलू सप्लायारों से समय पर सप्लाई प्राप्त होने में परेशानी आई। उन्होंने चारो घरेलू उत्पादकों से सर्म्यक बनाए रखा मगर वे असफल रहे।
  - (iv) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान विजली कटौती, श्रम समस्या और गुणवत्ता समस्याओं के कारण घरेलू उत्पादकों को उनकी मांग/अनुसूची अनुसार सप्लाई देने में परेशानी हुई।
- (ख) 🛮 ड्राई सेल बैटरी निर्माताओं के संगठन ने भी अपने विचार निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किए हैं :—
  - (i) बिजली की कटौती, श्रम समस्या आदि और वार्षिक रखरखाव के लिए मैं. पन्यम द्वारा अपना संयत्र बंद कर दिए जाने से कम उत्पादन के कारण घरेलू उत्पादक घरेलू उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर सके ।
  - (ii) वर्ष 1996-97 के दौरान आयात में वृद्धि के बावजूद टैसिल के अलावा घरेलू उत्पादक या तो अपना उत्पादन बढ़ाने में या अपने उत्पादन का स्तर बनाए रखने में समर्थ थे।
  - (iii) मै. टैसिल द्वारा एबी का उत्पादन या तो बिजली की कटौती या श्रम समस्या से कम हुआ आयात में वृद्धि के कारण नहीं।
  - (iv) बढ़े हुए आयात को उत्पादन में गिरावट का कारण नहीं माना जा सकता और इसीलिए बढ़े हुए आयात और क्षित में कोई कारण सम्बन्ध नहीं था।
  - (v) 1996-97 में घरेलू एबी उद्योग में गिरावट के मुख्य कारण बिजली की कटौती, श्रम समस्या, एसिटीलिन प्राप्त न होने के कारण उत्पादन में असफलता और गुणवत्ता की समस्याएं आदि थी जिसके कारण ड्राई सेल के घरेलू निर्माताओं के सामने उच्च स्तर को बरकरार रखकर एक संतोषजनक लागत पर आयात करने, सीमा शुल्क के जरिए अपने माल की निकासी करने और क्रेडिट पत्रों आदि को खोलने आदि के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था।

- (vi) 1997-98 में कोई गम्भीर **शति नहीं हुई क्योंकि पन्यम और ओसवाल ने** उपने उत्पादन का पूर्व स्तर बनाए रखा। टेसिल के उत्पादन में गिरावट का कारण **विजली की कटौती और त्रम समस्याएं बीं। सैन्का द्वा**रा एबी की पूर्ती में गुणवत्ता की समस्या थी।
- (vii) बढ़े हुए आयात के अलावा बिजली की कटौती, बढ़ा हुआ बिजली का मूल्य, त्रम समस्या, कैल्सियम कारबाइड रूट आदि के जरिए उच्च लागत आदि ऐसे मुख्य कारण ये जो कि एवी के घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे थे।
- (viii) एबी के घरेलू उद्योग ने यह स्वीकार किया था कि कैल्सियम कारबाइड की कम सप्लाई, बिजली की कमी के कारण कम उत्पादन और अत्यधिक प्रतिशत में बिजली कटौती से एबी के उत्पादन में कमी के कारण आयात में वृद्धि हुई।
- (ix) पन्यम और टेसिल बिजली के सदुपयोग में अत्यधिक अनिपुण थे।
- (x) उन्नत प्रतियोगिताओं के साथ समायोजित करने के लिए रेखांकित करते हुए एबी के घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे केवल शैक्षणिक थे और वास्तव में कारबाइड रूट के कारण उनकी दक्षता में कोई सुधार नहीं होता।
- (xi) ऐण्टी डम्पिंग और रक्षोपाय उपायों को मिला दिया गया था।

# 5. महानिदेशक का निष्कर्ष

(i) इन निष्कवों पर पहुँचने से पहले **घरेलू उद्योगों, निर्यातकों, जाधानी राजदूताबास, उपभोक्ताओं, आयातकों और** अन्य रूचि रखने वाले पक्षों के निवेदनों पर विचार एवं परीक्षण किया गया और इन निष्क**वों में समुचित स्थामों पर उन पर ध्यान रखा** गया है । क्षेत्राधिकार

(ii) एडीसीबीएम ने महानिदेशक के क्षेत्राधिकार जैसी कुछ प्रारंभिक आपित्तयाँ उठाई हैं। ऐसा उचित समझा गया है कि सबसे पहले इन प्रारंभिक मुद्दों पर विचार किया जाए। ए.डी.सी.बी.एम. ने रक्षोपाय पर सहमति (ए.ओ.एस.) के कुछ प्रावधानों जैसे अनुच्छेद 12.3 और अनुच्छेद 8.2 का हवाला दिया है ओर तर्क दिया है कि भारत में लागू नियम यह कार्य प्रणाली प्रदान नहीं करते हैं इसलिए यह जाँच, अनुच्छेद 19 (गैट) में निहित सिद्धांतों के विपरीत है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि छूट का स्तर/दूसरे देशों को प्रस्तावित व्यापार क्षतिपूर्ति को तय करने के लिए महानिदेशक सक्षम नहीं हैं और आगे यह भी कि भारत सरकार के व्यापार आर्बटन नियम 1961 के अनुसार टैरिफ और गैर टैरिफ रोध सहित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नीति से संबंधित सभी मामले वाण्यि मंत्रालय (एम.ओ.सी.) के कार्यक्षेत्र में आते हैं और वित्त मंत्रालय (एम. ओ.एफ.) इस विवय में कार्रवाई करने हेतु सक्षम नहीं है। ए.डी.सी.बी.एम. ने निवेदन किया है कि वित्त मंत्रालय के अधीन महानिदेशक समुचित प्रिधिकारी नहीं है और इस मामले में कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए उनका कोई क्षेत्राधिकार नहीं है।

ए.ओ.एस. का अनुच्छेद 12.3 और अनुच्छेद 8.2 निम्नलिखित प्रदान करता है :---अनुच्छेद 12.3

अनुच्छेद 8 के पैरा 1 में दिए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीकों पर सहमित तक पहुँचने तथा उपायों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए पैरा 2 के अधीन प्रदत्त सूचनाओं की समीक्षा की दृष्टि से अन्य बातों के साथ-साथ, रक्षोपाय के उपायों को विस्तारित या लागू करने हेतु प्रस्ताव करने वाला सदस्य, संबंधित उत्पाद के निर्यातक के रूप में पर्याप्त रूचि रखने वाले उन सदस्यों के साथ पूर्व परामर्श के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा।

# अमुच्छेद 8.2

यदि अनुच्छेद 12 के पैरा 3 के अन्तर्गत विचार-विमर्श में 30 दिन के अन्दर कोई समझौता नहीं हो पाता है तो प्रभावित निर्यातक सदस्य, उपायों को लागू करने के 90 दिन के भीतर, 30 दिन की अवधि बीत जाने के बाद उस दिन से जिस दिन इस तरह के निलम्बन की लिखित सूचना काउन्सिल फार ट्रेड इन गुड्स को मिली, पर्याप्त समतुल्य छूट को लागू करने को निलम्बित करने के लिए स्वतंत्र होगा था गैट 1994 के अधीन अन्य किसी दायित्व को जीकि सुरक्षोपाय उपाय लेने वाले सदस्य के अनुरूप स्वीकार किया गया है जिसका निलम्बन काउन्सिल फार ट्रेड इन गुड्स अननुमोदित नहीं करती है।

ए ओ एस के उपरोक्त प्रावधान ए ओ एस के अधीन परामर्शी और क्षतिपूर्ति दायित्वों के बारे में विचार करते हैं। ये वे दायित्व हैं जिनका वहन, आयातक देशों की सरकारों (डब्ल्यू टी ओ के सदस्य के रूप में संदर्भित) को डबल्यू टी ओ के सदस्य के रूप में तथा साथ आन्य सदस्यों को करना पड़ता है। ए ओ एस के अनुच्छेद 3 के पैरा 1 में अनुबंध है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामले की जांच करने के बाद ही कोई सदस्य रक्षोपाय उपायों के लिए आवेदन कर सकता है। इस प्रकार रक्षोपाय उपायों को लागू करने या इसके विस्तार के लिए आयातकर्ता सदस्य की सक्षम प्राधिकारी द्वारा जॉच करना एक पूर्व-शर्त हैं। दिनांक 28-11-97 को जारी नोटिस में महानिदेशक ने जांच की इस प्रक्रिया को शुरू करना प्रस्तावित किया है न कि रक्षोपाय उपायों को लागू या विस्तारित करना। सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियमावली 1997 (एस जी डी नियमावली) के नियम 4 के अधीन महानिदेशक को अनित्तम या अंतिम रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने से संबंधित सिफारिश करने के लिए दायित्व सौंपा गया है। फिर भी रक्षोपाय शुल्क केवल केन्द्र सरकार द्वारा लागू किया जा सकता है, इसी तरह दूसरे देशों को दिए जाने वाली छूट/व्यापार क्षति पूर्ति के स्तर को तय करने का दायित्व सदस्य यथा आयातक देश की सरकार पर है न कि जाँच करने वाले प्राधिकारी, इस मामले में महानिदेशक, पर है।

जहाँ तक वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत महानिदेशक का संबंध है, महानिदेशक पद का सूजन अधिसूचना सं. 35/97-एन. टी-सीमा शुल्क दिनांक 29 जुलाई 1997 द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित एस.जी.डी. नियमों द्वारा किया गया है। जिसे संसद द्वारा पारित किये गये अधिनियम, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 8 बी के अधीन अधिनियमित किया गया है। एस.जी.डी. नियमों के नियम 3 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक ऐसे अधिकारी को महानिदेशक (रक्षोपाय) नियुक्त कर सकती है जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का न हो या ऐसे किसी अन्य अधिकारी को जिसे यह सरकार उपयुक्त समझे। महानिदेशक (रक्षोपाय) को यहां इसके बाद इन नियमों के उद्देश्यों के लिए महानिदेशक के रूप में संदर्भित किया गया है। इसके अनुसार ही केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना सं. 45/97-सीमाशृल्क (एन. टी.) दिनांक 16 सितम्बर 1997 द्वारा महानिदेशक को नियुक्त किया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने पर वह महानिदेशक का क्षेत्राधिकार है कि वे रक्षोपाय जांच कार्य संभालें और रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिशें प्रस्तुत करें।

## (III) जांच के अधीन उत्पाद:—

जांच के अधीन उत्पाद एसिटिलिन ब्लैंक है तो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (सीटीए) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 2803.00 के अधीन और भारतीय व्यापार वर्गीकरण (आई.टी.सी.) के शीर्ष 28030001 के अधीन आता है, एबी कार्बन ब्लैंक की एक श्रेणी है जो भारत में ड्राई सेल में मैग्नीज डाई-आक्साईड की चालकता को उन्तत करने के काम में आता है। भारत में एबी, कैल्सियम कार्बाइड रूट और पेट्रोकेमिकल्स रूट के माध्यम से निर्मित होता है। कैल्सियम कार्बाइड रूट में, एसिटिलीन गैस, कैल्सियम कार्बाइड के पानी के साथ प्रतिक्रिया करने से बनती है। कैल्सियम कार्बाइड रूट के माध्यम से निर्मित एबी से मंहगा और गुणवत्ता में अधिक अच्छा है। भारत में निर्मित एबी का 90% से अधिक का उत्पादन कैल्सियम कार्बाइड रूट के माध्यम से निर्मित एबी से मंहगा और गुणवत्ता में अधिक अच्छा है। भारत में निर्मित एबी का 90% से अधिक का उत्पादन कैल्सियम कार्बाइड रूट के माध्यम से होता है। भारत में घरेलू उत्पादकों द्वारा निर्मित एबी को केन्द्रीय शुल्क टैरिफ के शीर्ष 2803.00 के अधीन वर्गीकृत किया गया है। घरेलू निर्मित एबी भी आयातित एबी की तरह एक जैसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग होता है और एस जी डी नियमावली के तात्पयों के अन्तर्गत, आयातित ए.बी. उन्हीं वस्तुओं जैसा है।

# (IV) घरेलू उद्योग

भारत में ए बी के चार घरेलू उत्पाद हैं यथा : मैं. टेसिल केमिकल्स एण्ड हाडड्रोपावर लिमिटेड, मैं. पन्यम सीमेंट एण्ड मिनरल्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, मैसर्स सेंका कार्बन प्राइवेट लि. और मै. ओसवाल पेट्रो केमिकल्स। जहां मैं. टेसिल, मैं. पन्यम और मैं. सेंका, ए बी का उत्पादन कैल्सियम कार्बाइड रूट से करते हैं वहीं मैं. ओसवाल ए बी का उत्पादन पेट्रो केमिकल्स रूट से करते हैं। सम्पूर्ण घरेलू उत्पादन करने वाले सभी चारों घरेलू उत्पादकों द्वारा आवेदन किया गया है। कैल्सियम कार्बाइड को कच्चे माल की तरह प्रयोग करने की निर्माण सुविधा दक्षिणी राज्यों जैसे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में है क्योंकि इन क्षेत्रों में कार्बाइड की प्राप्ति बड़े स्तर पर होती है। मैं. ओसवाल की उत्पादन सुविधा चेम्बूर, मुम्बई में है।

## (V) बढ़ा हुआ आयात

भारत में ए बी का आयात 1970 के बाद और 1980 के पूर्व हो रहा था। फिर भी 80 के दशक के मध्य से 1996 के आरंभ तक व्यःवहारिक रूप में कम मात्रा में ही ए. बी. का आयात हुआ। 1994-95 में 8.3 मी. टन से बढ़कर 1995-96 में 71 मी. टन और 1996-97 में 841.06 मी. टन का आयात हो गया। चालू वर्ष (अप्रैल-जुलाई) में 250.57 मी. टन का आयात हुआ। इस समय के दौरान घरेलू उत्पादन 3355.43 मी. टन, 3570.075 मी. टन, 3274.62 मी. टन, और 848 मी. टन था। (अप्रैल-सितम्बर 97 के आंकड़ों के आधार पर 1272.25 मी. टन के आधार पर गणना की गयी) इस प्रकार घरेलू उत्पादन की तुलना में कुल मिलाकर आयात में वृद्धि हुई है। घरेलू उत्पादन की तुलना में आयात जो कि 1994-95 में 0.24 %, 1995-96 में 1.98% से बढ़कर 1996-97 में 25.68% और 1997-98 में (अप्रैल-जुलाई) में 29.54% पहुँच गया। नीचे दी गई सारणी घरेलू उत्पादन की वार्षिक आधार पर स्थापित क्षमता, उत्पादन, बिक्की आयात और घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में आयात और कुल उपभोग को दशांती है :—

वर्ष	स्थापित क्षमता प्रतिवर्ष मी.टन	उत्पादन मी,टन	ब्रिकी मी.टन	आयात मी.टन	घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में आयात	आभासी उपभोग के प्रतिशत के रूप में आयात मी.टन
1994-95	5300	3355.43	3422	8.3	0.24	0.24
1995-96	5300	3570.07	3574	71.0	1.98	1.95
1996-97	5600	3274.62	3017	841.06	25.68	21.80
1997-98	5600	1272.25 अप्रैल सितम्बर	1291	250.57 अप्रैल- सितम्बर	29.54	22.81 अप्रैल- सितम्बर

इस तरह घरेलू उत्पादन की तुलना में और वास्तविक रूप में भारत में ए बी का आयात बढ़ा है।

## (VI) गम्भीर क्षति:--

आयातकों ने आरोप लगाया है कि 1996-97 के दौरान वार्षिक रख-रखाव के लिए मैं. पन्यन के संयंत्र के बन्द रहने और श्रम समस्या के कारण उत्पादन में गिरावट के कारण ए. बी. के घरेलू उत्पादक घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए सक्षम नहीं थे। दूसरी ओर, घरेलू उत्पादकों ने स्वीकार किया है कि घरेलू कीमतों को घटाने के लिए आयात की कीमतों में तेजी से कमी हुई थी जहाँ अक्टूबर, 1996 में कीमतें लगभग 2500 अमेरिकी डालर प्रति मी. टन पड़ती थी, जिसकी भारतीय ग्राहकों को अवतरण कीमत 1,28,000/- रूपये प्रति मी. टन पड़ती थी। वहीं अप्रैल, 1997 में कीमतें घटकर 1700 अमेरिकी

डालर प्रति मी. टन हो गयी, जिसकी अवतरण कीमत 83000/- रुपये प्रति मी. टन हो गयी। ए. बी. के उपयोग कर्ता/आयात कर्ता घरेलू उत्पादकों से माँग करते रहे हैं कि वे अपनी कीमतें आयात की कीमतों के अनुरूप कम करें और उन्होंने यह भी धमकी दी थी कि यदि कीमतें कम नहीं की जायेंगी तो वे उनसे सामान लेना कम कर देंगे।

आयातकों द्वारा आयात के संबंध में प्रस्तुत की गयी सूचनओं से ज्ञात होता है कि भारत में प्रवेश करने वाले ए.बी. के आयात मूल्य में मई, 96 में 2654 अमेरिकन डालर प्रति मी. टन से घटकर अक्टूबर, 96 में 2300 अमेरिकन डालर, अप्रैल, 1997 में 2000 अमेरिकन डालर और अक्टूबर, 1997 में 1800 अमेरिकन डालर हो गया। इस प्रकार आयातित ए.बी. की अवतरण कीमत 1996-97 और 1997-98 के दौरान कम ही होती गयी है। इसका उपभोक्ता उद्योग द्वारा प्रापण फैसलों पर स्वाभाविक रूप से प्रभाव पड़ा होगा क्योंकि आपूर्ति के स्नोत को निर्धारित करने में ग्राहकों के लिए मूल्य सबसे महत्वपूर्ण कारक था जैसा कि आयात के आंकड़ों से स्पष्ट है कि वह 1995-96 में 71 मी. टन से बढ़कर 841.06 मी. टन व 1997-98 के प्रथम चार महीनों में 250.5 मी. टन हो गया।

इस अविध में भरेलू उत्पादन 1995-96 में 3570.07 मी. टन से गिरकर 1996-97 में 3274.62 मी. टन और 1997-98 के प्रथम छः महीनों में 1272.25 मी. टन हो गया। इस अविध में क्षमता का उपयोग 63.75% से घटकर क्रमशः 58.46% और 45.42% हो गया। घरेलू उत्पादन के अंश, जो इस अविध में 98.05% से घटकर क्रमशः 78.2% और 77.19% हो गया, इस अंश की कीमन पर आभासी उपभोग में आयातित ए.बी. का अंश 1995-96 में 1.95% से बढ़कर 1996-97 में 21.8% और 1997-98 के प्रथम चार महीनों में 22.81% हो गया। इसी समय घरेलू उत्पादकों का स्टाक 1995-96 में 50.71 से घटकर 1996-97 में 308.12 मी. टन हो गया। भारत में ए.बी. की वार्षिक मांग लगभग 4000 मी. टन है। किन्तु इसके विरुद्ध, घरेलू उत्पादकों की स्थापना क्षमता 5600 मी. टन है जो ए.बी. की घरेलू मांग से 40% ऊपर और अधिक है। घरेलू उत्पादकों में घरेलू मांग से 40% अधिक की क्षमता बी और उनके पास 1996-97 में 308.12 मी. टन का स्टाक था जो स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि घरेलू उत्पादकों की बिक्री मूल्य से कम मूल्य पर प्रवेश करने वाले बढ़े हुए आयात के सामने घरेलू उत्पादकों ने अपना बाजार खो दिया।

1994-95 में 3422 मीट्रिक टन, 1995-96 में 3574 मीट्रिक टन और 1996-97 में 3017 मीट्रिक टन की बिक्री की तुलना में बरेलू उत्पादकों ने सामूहिक रूप से वर्ष 1997-98 (अप्रैल-सितम्बर) की अवधि के दौरान केवल 1291 मीट्रिक टन की बिक्री ही दर्ज की। वर्ष 1997-98 में बड़े अनुपात में बिक्री मैं, पन्यम द्वारा की गयी जिन्होंने 936.7 मीट्रिक टन ए.बी. का घटे हुए औसत विक्रय मूल्य पर बिक्री किया जो 1996-97 में रु. 114417 प्रति मी. टन. से गिरकर 1997-98 में रु. 99967 प्रति मी. ट. हो गया जिससे लगभग 12.63% की कमी हुई। दूसरे भी 1996-97 की जगह 1997-98 में अपने औसत विक्रय मूल्य को कम करके केवल छोटी मात्राओं में ही बिक्री कर सके। यह उस परिप्रेक्ष्य में हुआ जबकि बिजली की लागत, जिसका ए.बी. के उत्पादन की लागत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, 0.95 रुपये प्रति-यूनिट से बढ़कर 2.80 रुपये प्रति यूनिट हो गयी थी जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत बढ़ गयी। घरेलू उत्पादक उत्पादन की बढ़ी हुई लागत के समक्ष अपने विक्रय मूल्य को घटाकर अपने घटे हुए बाजार अंश को बनाये रख सके। मैं. टेसिल ने पहले ही अपने उत्पादन को अस्थाई रूप से अगस्त 1997 से बन्द कर दिया है और दूसरे भी मानव दिवसों की गंभीर क्षति का सामना कर रहे हैं।

अतः घरेलू उत्पादकों को ए.बी. के बढ़े हुए आयात के कारण उत्पादन में क्षति, विक्रय मूल्य में कमी, माल की सूची में वृद्धि, बिक्री मूल्य में कमी और रोजगार में क्षति उठानी पड़ी है। इसलिए, बढ़े हुए आयात ने घरेलू उत्पादकों को क्षति पहुंचाई है और इससे उन्हें आगे भी क्षति पहुंचने का खतरा है। (VII) बढ़े हुए आयात के अतिरिक्त अन्य कारकों का प्रभाव:—

चार घरेलू उत्पादकों में से एक मैं. पन्यम ने 1996-97 में वार्षिक अनुरक्षण के लिए अपने संयंत्र को बन्द कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि वह अधिकांश संयंत्र की क्षमता के उपयोग पर कोई प्रतिकृल प्रभाव नहीं पड़ता है जिसे सामान्यतः वार्षिक अनुरक्षण आदि के लिए काम बन्द कर देने को ध्यान में रखना चाहिए।

मैं, टेसिल ने 1996-97 में विद्युत कटौती और ब्रम संबंधी कुछ समस्याओं का सामना किया था। उन्होंने श्रम संबंधी अपनी समस्याओं को सुलङ्गाया और नवम्बर 1996 में पूर्ण उत्पादन पुन: आरंभ किया। तथापि मैं. टेसिल की घरेलू उद्योग की 5600 मी. टन की कुल स्थापित क्षमता में से 2000 मी. टन की स्थापित क्षमता है, यहां तक कि पिछले वर्ष 1995-96 के दौरान उन्होंने केवल 1031.8 मी. टन का उत्पादन किया जो कि उनकी स्थापित क्षमता का 51.59% है अर्थात यह उनके केवल 6 माह का उत्पादन है। घरेलू उद्योग के पास घरेलू जरूरत से 40% अधिक सरप्लस क्षमता है। और संगठित रूप से जहां 1995-96 में घरेलू उत्पादकों के पास 50.71 मी. टन का भण्डार था वहां यह 1996-97 में 308 मी. टन तक बढ़ गया। यह विचारणीय नहीं है कि इन तथ्यों ने घरेलू जरूरत की पूरा करने के लिए घरेलू उत्पादन की पूर्ण उपलब्धता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव डाला।

जहां तक ए.बी. के भरेलू उत्पादन की गुणवत्ता से संबंधित आरोपों का प्रश्न है, घरेलू उत्पादन की गुणवत्ता को उपभोगी उद्योग द्वारा स्वीकार किया गया है। वास्तव में मै. सेंका ने मै. इण्डो नेशनल लिमिटेड से दिनांक 2-9-92 एवं 15-12-95 को उत्पादन की गुणवत्ता, मात्रा और त्वरित सेवा के लिए प्रमाण-पत्र प्राप्त किए और इस कार्य के लिए उन्होंने 1996-97 के लिए योग्यता-पुरस्कार भी प्राप्त किया।

ए.बी. के कुछ घरेलू उत्पादकों ने बैल्जियम, तुर्की और ईरान को एबी का निर्यात किया। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है।

एडी सी बी एम ने रक्षोपाय उपायों और इन्टी डम्पिंग उपायों को एक साथ मिलाने का भी आरोप लगाया है। तथापि ए डी सी बी एम ने अपने दावों की सत्यता को साबित करने के लिए और ए बी के डम्पिंग के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया अतः इसे निरस्त किया जाता है।

## (VIII) सकारात्मक समायोजन के लिए प्रतिबद्धता :

चारों घरेलू उत्पादकों में से मै. टेसिल और मै. पन्यम के पास अपने कैल्सियम कार्बाइड संयंत्र है। कैल्सियम कार्बाइड, एक गहन विद्युत उत्पादक होने के कारण मै. टेसिल ने 7.5 मैगावाट और 15 मैगावाट की स्थापित क्षमता के दो हाइड्रो विद्युत परियोजना का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया है जो और अधिक किफायती होगी तथा जिससे कि कैल्सियम कार्बाइड तथा तदुपरान्त ए.बी. की समग्र उत्पादन की लागत में कमी होगी।

- मैं. सेंका पहले ही अपने उत्पाद की लागत को प्रभावी बनाने के लिए और एसिटिलिन गैस प्राप्त कर ए.बी. में परिवर्तित करने के लिए पैट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज से विचार विमर्श कर रहे हैं।
  - मै, पुन्यम भी मै, सेंका के प्रस्तावित उपायों की तरह उसी तरह की कार्रवाई कर रहे हैं।
- मैं. ओसवाल, अपने एथिलिन संयंत्र से एक उप-उत्पाद के रूप में प्राप्त एसिटिलीन गैस की बढ़ी हुई मात्रा प्राप्त कर ए.बी. के वर्धित उत्पादन की आशा कर रहे हैं।

ये सभी योजनाएं चार वर्ष की अविध में पूरी होने का अनुमान है और इससे घरेलू उद्योगों के प्रतियोगी बनने की संभावना है।

## (IX) प्रत्येक देश की आयात में हिस्सेदारी:

1996-97 में विभिन्न निर्यातक देशों की भारत में ए.बी के कुल आयात में हिस्सेदारी निम्नलिखित है :—

देश	मात्रा मी. टन	हिस्सेदारी का प्रतिशत
बैल्जियम	62.10	7.38%
पी. आर. चीन	93.50	11.11%
क्रांस	255. <del>44</del>	30.36%
जापान	180.236	21.42%
सिंगापुर	128.70	15.29%
दी पिलीपिन्स	51.75	6.15%
साउथ अफ्रीका	59.54	7.07%
कुल =	841.27	

#### (X) विषम परिस्थितियां :

चालू वर्ष 1997-98 के प्रथम 6 माह में घरेलू उद्योग के उत्पादन में बहुत कमी आई है। यह कमी 1996-97 के 3274.62 मी. अन की तुलना में कम हो कर 1272.25 मी. उन रह गयी जोकि वर्ष 1996-97 की तुलना में अनुपातत: 22.3% की हानि है। घरेलू उत्पादकों में से एक मै. टेसिल ने जिसकी स्थापित क्षमता 2000 मी. टन है, ने अपने उत्पादन को अगस्त 97 से निलंबित कर दिया है और दूसरी इकाईयों श्रम दिनों की गम्भीर समस्या का सामना कर रही है। चस्तु सूची बढ़ रही है। घरेलू उत्पादकों की बिक्री का हनन हो गया है और बाजार में वे केवल अपनी बिक्री का घटा हुआ हिस्सा बनाये रखने में तभी सफल हुए जब उन्होंने अपना बिक्री मूल्य उत्पादन लागत से भी कम कर दिया है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए इस तरह की गम्भीर परिस्थितियां सामने आई हैं जो कि मरेलू उत्पादकों को क्षति से बचाने के लिए तत्काल अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क लगाने को सही उहराती है। यदि रक्षोपाय उपायों का लगाने में देरी की जाती है तो इससे हुई क्षति की पूर्ति संभव नहीं होगी।

## (XI) निष्कर्ष और सिफारिश:

उपरोक्त प्राथमिक निष्कर्षों के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि ए.बी, के वर्धित आयात से ए.बी. के घरेलू उत्पादकों को गम्भीर क्षति हुई है और क्षति होने की आशंका है, गम्भीर परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिससे जहाँ रक्षोपाय उपाय लगाने में जरा भी देरी से ऐसा नुकसान हो सकता है जिसकी पूर्ति मुश्किल होगी। गम्भीर क्षति की अंतिम अवधारणा को विलम्बित रखते हुए 200 दिन की अवधि के लिए तत्काल से अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क लगाया जाना आवश्यक है।

घरेलू उत्पादकों द्वारा ए. बी. के. उत्पादन की औसत लागत (गोपनीय), उपयुक्त लाभांश, आयात शुल्कों का वर्तमान स्तर और ए. बी. का औसत आयात मूल्य को ध्यान में रखते हुए 19500 रु. प्रति मी. टन की दर से जो कि घरेलू उद्योग के लाभ हेतु कम से कम आवश्यक है, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (आई टी सी के 28030001) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 2803.00 के अधीन आने वाली एसिटिलीन ब्लैक पर शुल्क लगाने की संस्तुति की जानी है।

#### 6. आगे की प्रक्रिया:

- (i) विभिन्न पक्षों द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन किया जा सकता है, जहाँ आवश्यक है, जिसके लिए उन्हें अलग से सूचित किया जाएगा।
- (ii) अंतिम अवधारणा से पूर्व आने वाले समय में सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जाएगी जिसके लिए तिथि की सूचना अलग से दी जाएगी।
- (iii) इन प्राथमिक निष्कर्षों पर इच्छुक पक्ष अपना दृष्टिकोण अधोहस्ताक्षरी को 9-3-98 तक प्रेषित कर दें।

[फा. सं. एस जी/आई एन वी/1/97] आर. के. गुप्ता, महानिदेशक (रक्षोपाय)

# DIRECTOR GENERAL (SAFEGUARDS) NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 1998

Subject: Safeguard investigation concerning imports of Acetylene Black (AB)—Preliminary Findings

G.S.R. 68(E).—SG/INV/1/97 dated 27 January 1998 - Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 and the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 thereof;

## 1.Procedure

i) The Notice of Initiation of Safeguard investigation concerning imports of Acetylene Black into India was issued on 28 November 1997 and was published in the Gazette of India Extraordinary on the same day. A copy of the Notice was also sent to all known interested parties as under:

## DOMESTIC PRODUCERS

1.M/s Tecil Chemicals & Hydro Power Ltd.

Mumbai - 400001

2.M/s Panyam Cements & Mineral Industries Ltd.

Hyderabad - 500029

3.M/s Senka Carbon Pvt Ltd.

Chennai - 600090

4.M/s Oswal Petro Chemicals

Mumbai- 400074

## **IMPORTERS**

1. M/s Eveready Industries India ltd

Calcutta- 700019

2. M/s Indo National Ltd.

Chennai - 600034

3. M/s Lakhanpal National Ltd.

Baroda- 390010

4. M/s Geep Industrial Syndicate Ltd.

Allahabad-211001

#### **EXPORTERS**

1.M/s Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha (Denka) Japan

2.M/s Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha (Denka)(DSPL) Singapore

3.M/s Karbochem

South Africa.

4. The Society Du Noir d' Acetylene

France

5.M/s Matsushita Electronic Indl. Co. Ltd.

Japan-Agents for Chinese Exporter

6.M/s MCCI Corporation

Philippines.

7. M/s M.M.M.S.A

Belgium

- ii) A Copy of the Notice was also sent to governments of exporting countries through their embassies in New Delhi.
- iii) Questionnaires were also sent, on the same day, to all known domestic producers and importers and they were asked to submit their response within 37 days. Request for an extension of time to submit their replies were made by the following parties:
  - M/s Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha, Japan.
  - 2. DSPL, Singapore
  - 3. M/s M.M.M.S.A ,Belgium
  - 4. M/s Karbochem, South Africa
  - 5. The Society Du Noir d' Acetylene, France, and
  - 5. All the four importers named above

Keeping their request in mind and the need to complete the investigation within the statutory time period, an extension up to 19 January 1998 was allowed and the parties concerned were accordingly informed.

- iv) The Chemicals Industries Association of India, Chennai, requested to be considered as an interested party which was acceded to.
- v) Replies to the Notice dated 28 November 1997 and questionnaires have been received from three domestic producers namely M/s Tecil, M/S Panyam and M/S Senka, all the four importers named above and exporters namely M/s Kagaku Kogyo Kaisha, DSPL, M.M.S.A, Karbochem and Society Du Noir.
- vi) A reply to the Notice dated 28<sup>th</sup> November, 1997 has also been filed on behalf of the Association of Dry Cell Batteries Manufacturers (ADCBM). The ADCBM neither figured in the application filed by the domestic producers nor did it make a request for being considered as an Interested Party, in terms of paragraph 10 of the Notice dated 28th November, 1997. Notwithstanding the above, the issues raised by ADCBM in their reply have been dealt with at appropriate places.

31792198-2.

# 2. Views of the domestic industry

The domestic producers have made the following major points:

- a) Their product Acetylene Black (AB) was a ruperior variety of carbon black and was as per IS 12178 of 1987, more or less identical and comparable to Japanese specification J.I.S:1469-1984 and other international specifications
- b) AB was mainly used in the manufacture of Dry Cell Batteries and their customers were manufacturers of dry cell batteries
- c) Over 90% of AB was manufactured through the calcium carbide route. The major item contributing to the cost of carbide was power which had gone up from Rs.0.95 per unit in 1988-89 to Rs.2.80 per unit presently and hence the cost of production of AB was going up.
- d) They had been meeting the demand of dry cell batteries manufacturers till 1995-96 and there were practically little imports of AB. A sudden surge in the import of AB commenced in the year 1996-97 and their customers reduced their off take of AB from them.
- e) The CIF import price of AB had gone down from USD 2500/MT in October, 1996 to USD 1700/MT in 1997-98 and there are indication of further reduction in import prices.
- f) All the dry cell manufacturers had been in communication with them to reduce prices of their AB under the pretext that imported AB from Japan, South Africa and Phillipines and other countries was cheaper. In fact they had threatened to reduce the off take of AB from the indigenous manufacturers on price consideration alone.
- g) M/s. Indo National Ltd. had issued a certificate to M/s Senka in 1992 that they were quite satisfied with the consistency in their quality, quantity and prompt' service.

## 3. Views of the exporters / governments of exporting countries

The exporters of AB to India have expressed the following views:

- (a) Societe du Noir d' Acetylene, France
- (i) They were exporting AB to India in 1980-85 despite high customs duty because domestic production at that time was not sufficient to meet the Indian market requirement.
- (ii) In 1987-88 they stopped exporting AB because of very low export price and level of domestic production of AB.
- (iii) During 1996 they exported AB into India because domestic producers were facing production problem (lack of electricity) and stopped export to India by the end of 1996 due to strong price competition.

# (b) Denki Kagaku Kogyo kabushiki Kaisha (Denka)

- (i) Denka, Japan manufactured AB through calcium carbide route and DSPL, Singapore through Petrochemical route.
- (ii) There was no increase in imports and no lowering of prices so as to cause serious injury to the domestic industry.
- (iii) The price of imports into India were in accordance with internationally prevailing selling price and not particularly low as compared to international standards.
  - (iv)Decrease in domestic production had not been drastic. The decrease could be attributed to reasons other than the increased exports.
- (c) The Embassy of Japan, New Delhi has mentioned that it will make necessary comments in due course.

# 4. Views of the importers

The domestic users of AB who are also importers of AB have expressed their views as under:-

- (a) M/s Geep industrial Syndicate Ltd., have expressed their views as under:
- (i) They manufactured Dry Cell Batteries and AB was used as raw material
- (ii) Till March 96, their entire requirement of AB was being fulfilled by domestic suppliers
- (iii) They faced problem in getting timely supplies from domestic suppliers from April, 1996. They seriously approached all the four domestic producers for the supply, but failed.
- (iv) The domestic producers failed to make supplies as per their requirement /schedule during the year 1996-97 and 1997-98 due to power cut, labour problems and quality problems.
- (b) The Association of Dry Cell Batteries Manufacturers has also expressed their views as under:
- (i) Domestic producers were not able to meet the requirement of domestic users because of less production due to power cut, labour problems etc. and shut down of the plant by M/s Panyam for annual maintenance.
- (ii) Despite the increase in imports during 1996-97, the domestic producers except Tecil were able either to increase their production or to maintain their level of production.
- (iii) Production of AB by M/s Tecil went down either because of power cut or labour trouble and not because of increase in imports.
- (iv) Fall in production cannot be attributed to increased imports and hence there was no causal link between injury and increased imports.

31791/98-3

- (v) Presence of severe power cuts, labour problems, inability to produce due to non-availability of Acetylene and quality problems had been the reasons for the ills of domestic AB industry in 1996-97, which left the Dry Cell Manufacturers with no other option but to resort to import at considerable cost by way of maintaining high inventory levels, clearance of consignments through customs, opening of letters of credit etc.
- (vi) There was no serious injury in 1997-98 also because Panyam and Oswal had almost retained the same level of production. Fall in production of Tecil was due to power cuts and labour problems. There was quality problem in the supply of AB by Senka.
- (vii) Power cuts, increased power tariffs, labour problems, high cost through calcium carbide route etc. were the factors which were causing injury to the domestic AB industry instead of increased imports.
- (viii) Domestic AB industry had admitted that fall in production of AB due to short supply of calcium carbide, a power intensive product due to power shortage and high percentage of power cuts was the cause of increased imports.
- (ix) Panyam and Tecil were highly inefficient in energy usage.
- (a) The claims made by the domestic AB industry outlining the claims made by their to adjust to the improved competition were only academic and would not in their result in their improved efficiency because of the carbide route.
- (xi) \*trti-dumping and Safeguard Measures have been mixed up.

# 5. Findings of the DG

i) The submissions made by the domestic producers, the exporters, the Embassy of Japan, were/importers and other interested parties were examined and considered while arriving at these findings, and have been dealt with at appropriate places in these findings.

## <u>Jurisdiction</u>

ii) The ADCBM have raised certain preliminary objections as to the jurisdiction of the Director-General (DG). It is considered appropriate to deal with these preliminary issues first. The ADCBM has referred to certain provisions of the Agreement on Safeguards (AOS) namely Article 12.3 and Article 8.2 and has contended that the Rules enacted in India have not provided for these mechanisms and hence the investigation is contrary to the principles laid down in Article XIX (of GATT). They have also alleged that the DG is not competent to decide the level of concessions/ trade compensation to be offered to other countries and further that according to the Allocation of Business Rules, 1961 of the Govt. of India, all matters relating to International Trade Policy including tariff and non-tariff barriers are within the purview of the Ministry of Commerce(MOC) and the Ministry of Finance (MOF) is not competent to deal with the subject. The ADCBM has submitted that the DG under the MOF is not the proper authority and has no jurisdiction to proceed further in this matter.

# Article 12.3 and Article 8.2 of the AOS provide as under:

## Article 12.3

A Member proposing to apply or extend a safeguard measure shall provide adequate opportunity for prior consultations with those Members having a substantial interest as exporters of the product concerned with a view to inter-alia, reviewing the information provided under paragraph 2, exchanging views on the measure and reaching an understanding on ways to achieve the objective set out in paragraph 1 of Article 8.

# Article 8.2

If no agreement is reached within 30 days in the consultation under paragraph 3 of Article 12, then the affected exporting Members shall be free, not later than 90 days after the measure is applied to suspend, upon the expiration of 30 days from the day on which written notice of such suspension is received by the Council for Trade in Goods, the application of substantially equivalent concessions or other obligations under GATT 1994, to the trade of the Member applying the safeguard measure, the suspension of which the Council for Trade in Goods does not disapprove.

The above provisions of the AOS deal with consultative and compensatory obligations under the AOS, which are the obligations cast on the governments of importing countries (referred to as 'Members' of WTO) as Members of WTO vis-à-vis other Members. Paragraph 1 of Article 3 of the AOS stipulates that a Member may apply a safeguard measure only following an investigation by the Competent Authorities of that Member. Thus, investigation by the competent authorities of the importing Member is a pre-condition for the application or extension of safeguard measures. What the DG has proposed to do by issuing the Notice dated 28 November, 1997 is to start this process of investigation and not to 'apply or extend' a safeguard measure. The DG, under Rule 4 of the Customs Tariff(Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997(SGD Rules) is entrusted with making recommendation regarding imposition of a provisional or final safeguard duty. The safeguard duty, however, may be applied only by the Central Govt. Similarly, the obligation to decide the level of concessions/trade compensation to be offered to other countries is cast on the 'Member' i.e. the government of the importing country and not on the investigating authority, the DG in this case.

As regards the DG functioning under the MOF, the DG is the creation of the SGD Rules, notified by the Central Govt. vide Notification No.35/97-NT-Custom dated 29<sup>th</sup> July, 1997 which have been enacted under Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975(51 of 1975) an Act passed by the Parliament. Under Rule 3 of the SGD Rules the Central Government may, by notification in the official Gazette appoint an officer not below the rank of Joint Secretary to The Government of India or such other officer as it may think fit as a Director General (Safeguard) hereinafter referred to as the Director General for the purpose of these rules. Accordingly the Central Government vide Notification No.45/97-Customs (NT) dated 16<sup>th</sup> September, 1997 has appointed the DG. Having been

appointed by the Central Govt., the DG has the jurisdiction to deal with the safeguard investigation and to make recommendations for imposition of safeguard duties to the Central Government.

## iii)The product under investigation:

The product under investigation is Acetylene Black falling under heading 2803.00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975(CTA) and under heading 28030001 of the Indian Trade Classification (ITC). The AB is a type of carbon black which is used to improve conductivity of Manganese Dioxide used in dry cells in India. AB in India is manufactured through the calcium carbide route and through petrochemicals route. In the calcium carbide route, Acetylene gas is produced by the reaction of calcium carbide with water. AB produced through calcium carbide route is costlier and better in quality than that produced through petrochemical route. In India over 90% of the production of AB is from calcium carbide route. AB manufactured by the domestic producers in India is classified under heading 2803.00 of the Central Excise Tariff. The domestically produced AB is used for the same purposes as the imported product and is a like article to the imported AB within the meaning of the SGD Rules.

## iv) Domestic Industry

There are four domestic producers of AB in India namely M/s. Tecil Chemicals & Hydro Power Ltd., M/s. Panyam Cements & Mineral Industries Ltd., M/s. Senka Carbon Private Ltd., and M/s. Oswal Petro Chemicals. While M/sTecil, M/s Panyam and M/s Senka produce AB through the calcium carbide route, M/s. Oswal produce AB through petrochemical route. The application has been made by all the four domestic producers who account for the entire domestic production. The manufacturing facilities using calcium carbide as a raw material have been located in the Southern States of India like Karnatako, Kerala and Tamilnadu since carbide availability in these areas is quite large. M/s. Oswal have their production facility located in Chembur, Mumbai.

# v)Increased Imports

AB was being imported in India in late 1970s and early 1980s. However, there have been practically imports of only small quantities since the middle of 80s till early 1996. The imports have increased from 8.3 MT in 1994-95 to 71 MT in 1995-96 and to 841.06 MT in 1996-97. During the current year (April-July) the imports have been 250.57 MT. During the corresponding period the domestic production has been 3355.43 MT, 3570.075 MT, 3274.62 MT and 848 MT (calculated on a pro-rata basis from the figures of 1272.25 MT for April-September, 1997). The imports, thus, have increased in absolute terms as well as compared to the domestic production. As compared to domestic production the imports which stood at 0.24% in 1994 95,1.98 in 1995-96 increased to 25.68% in 1996-97 and 29.54% in 1997-98 (April-July). The table below gives year-wise installed capacity, production, sales, imports and imports as a percentage of domestic production and apparent consumption.

YEAR	Installed capacity MT per annum	Production MT	Sales MT	Import MT	Import as a % of domestic production	Import as a % of Apparent Consumption MT
1994-95	5300	3355.43	3422	8.3	0.24	0.24
1995-96	5300	3570.07	3574	71.0	1.98	1.95
1996-97	5600	3274.62	3017	841.06	25.68	21.80
1997-98	5600	1272.25 (April- Sept.)	1291	250.57 (April- July)	29.54	22.81(April- July)

The imports of AB into India have thus increased in absolute terms as well as compared to the domestic production.

## vi) Serious Injury

The importers have alleged that the domestic producers of AB were not able to meet with the domestic requirement due to fall in production on account of labour problem and shut down of the plant of M/s Panyam for annual maintenance during 1996-97. The domestic producers on the other hand have submitted that the import prices had been reduced drastically to under-cut the domestic prices. While the price was nearly US\$ 2500/MT in October 1996 with the landed cost to the Indian customers at Rs 1,28,000 per MT, the price has been reduced to US\$ 1700/MT with the landed cost coming to Rs 83,000 per MT in April 1997. The users/importers of AB have been demanding the domestic producers to bring down their prices in line with the imported prices and have also threatened to reduce their off-take from them if the prices were not reduced.

It is seen from the information on imports furnished by the importers that import prices of AB entering into India have been falling down from US \$ 2654/MT in May 96 to US \$ 2300 in Oct 96 to US \$ 2000 in April 1997 and to US \$ 1800 in Oct 97. The landed prices of imported AB thus, have been coming down during the period 1996-97 and 1997-98. This would have naturally had an influence over the procurement decision by the user industry as the price was the most important factor for the customers in determining the source of supply which is obvious from the import figures which rose from 71 MT in 1995-96 to 841.06 MT and to 250.5 MT in the first four months of 1997-98.

The domestic production during this period fell down from 3570.07 MT in 1995-96 to 3274.62 MT in 1996-97 and to 1272.25 MT in the first six months of 1997-98. The capacity utilisation fell down from 63.75% to 58.46% and to 45.42% respectively during this period. The share of the imported AB in apparent consumption increased from 1.95% in 1995-96 to 21.8% in 1996-97 and to 22.81% in the first four months of 1997-98, at the cost of the share of the domestic production which fell down during the corresponding period from 98.05% to 78.2% and 77.19% respectively. At the same time the inventory with the domestic producers built up from 50.71 in 1995-96 to 308.12 MT in 1996-97. The annual requirement of AB in India is about 4000 MT. As against this, the installed

capacity of the domestic producers is 5600 MT which is 40% over and above the domestic requirement of AB. The domestic producers had an excess capacity to the extent of 40% over the domestic demand and they also carried stocks of 308.12 MT in 1996-97 which clearly establishes that the domestic producers lost their market to increased imports entering at prices lower than their selling prices.

During the year 1997-98 (April-Sept), the domestic producers collectively registered a sale of 1291 MT only as compared to a sale of 3422 MT in 1994-95, 3574 MT in 1995-96 and 3017 MT in 1996-97. The major proportion of the sales in 1997-98 was made by M/s Panyam who sold 936.7 MT of AB but only at a reduced average selling price which fell from Rs 114417/MT in 1996-97 to Rs 99967/MT in 1997-98, a reduction of about 12.63%. The others also could sell small quantities only by reducing their average selling prices in 1997-98 over 1996-97. This is in the background that the cost of power had gone up substantially from Rs0.95 per unit to Rs2.80 per unit, resulting in higher costs of production of Calcium Carbide. Calcium Carbide is a power intensive product and, therefore, the cost of power has a significant impact on the cost of production of Calcium-Carbide and thus on the cost of production of AB. To maintain even the reduced market share the domestic producers had to reduce their selling prices on the face of increasing cost of production resulting in operating losses. Consequently M/s Tecil have already suspended their production temporarily from August 1997 and others are facing severe loss of mandays.

The domestic producers, therefore have suffered loss of production, loss of sales, building up of inventories, reduction in selling prices and loss of employment caused by the increased imports of AB. The increased imports have, therefore, caused and have threatened to cause further injury to the domestic producers.

## vii)Effect of factors other than increased imports

Out of the four domestic producers, one namely M/s Panyam had shut down their plant for annual maintenance in 1996-97. This is considered to be a normal feature of most of the plants and not likely to have any adverse effect on capacity utilisation of the plant which should normally take into account shut down for annual maintenance etc.

M/s Tecil faced some problems in 1996-97 due to power cuts and labour. They settled their labour problems and resumed full production in November 1996. M/s Tecil, however, accounts for an installed capacity of 2000 MT out of the total installed capacity of 5600 MT of the domestic industry. Even during the previous year 1995-96, they produced only 1031.8 MT which works out to only 51.59% of their installed capacity i.e. only about six months' production. The domestic industry had a surplus capacity of 40% over and above the domestic requirement and in view of the domestic producers collectively carrying a stock of 50.71 MT in 1995-96 which increased to 308 MT in 1996-97, it is not considered that these factors may have had any significant effect on the over all availability of domestic production to meet the domestic requirement.

As regards the allegations concerning the quality of domestic production of AB, the quality of domestic production has all along been accepted by the user industry. In fact M/s Senka also received certificates on 2.9.92 and 15.12.95 from M/s Indo National Ltd. regarding their satisfaction with the consistency in Senka's quality, quantity and prompt service and also the merit award for 1996-97 to this effect. Some of the domestic producers have also exported AB to Belgium, Turkey and Iran. In view of these facts, there is no merit in these allegations.

The ADCBM have also alleged mixing up of Safeguard measures and Anti-Dumping measures. No evidence of dumping of AB, however has been produced by ADCBM to substantiate its claim and is accordingly rejected.

## viii) Commitment to make a positive adjustment

Out of the four domestic producers M/s Tecil and M/s Panyam have their captive Calcium Carbide plants. Calcium Carbide being a power intensive product M/s Tecil have started implementation of two Hydro Power projects with installed capacities of 7.5 mw and 15 mw which would prove more economical bringing down the overall cost of production of Calcium Carbide and in turn AB.

M/s Senka are already in discussion with Petrochemical Industry for getting acetylene gas for conversion into AB to make the product cost effective.

M/s Panyam are also taking similar steps as proposed by M/s Senka.

M/s Oswal are contemplating increased output of AB by increasing recovery of Acetylene Gas recovered as a by- product from their Ethylene plant.

All these plans are expected to be completed within a period of four years and are likely to make the domestic industry competitive.

## ix) Share in Imports of individual countries

Individual shares of various exporting countries in 1996-97 in the total imports of AB into India are as under:

Countries	Quantity MT/ Percentage Share			
Belgium	62.10	7.38%		
PR China	93.50	11.11%		
France	255.44	30.36%		
Japan	180.236	21.42%		
Singapore	128.70	15.29%		
The Philippines	51.75	6.15%		
South Africa	59.54	7.07%		
Total	841.27			

#### x) Critical Circumstances

The production of the domestic industry during the first six months of the current year 1997-98 has fallen down drastically to a level of 1272.25 MT from 3274.62 MT in 1996-97, which on a pro-rata basis amounts to a loss 22.3% over 1996-97. One of the domestic producers M/s Tecil with an installed capacity of 2000 MT has already suspended its production from August 1997 and the other units are facing severe loss of mandays. Inventory is building up. The domestic producers have lost sales and have been able to maintain a reduced share in the market only at the cost of reduction in their selling prices below their costs of production.

In view of the above, critical circumstances exist justifying imposition of provisional safeguard duties immediately in order to save the domestic producers from damage which it would be difficult to repair if the application of safeguard measures is delayed.

## xi) Conclusion and Recommendation

On the basis of the above preliminary findings it is concluded that the increased imports of AB have caused and have threatened to cause further serious injury to domestic producers of AB. Critical circumstances, where any delay in application of safeguard measures would cause damage which it would be difficult to repair, exist necessitating immediate application of provisional safeguard duty for a period of 200 days, pending a final determination of serious injury.

Considering the average cost of production of AB by the domestic producers (confidential), a reasonable profit margin, the present level of import duties and the average import prices of AB, safeguard duty @ Rs.19500 per MT, which is considered to be the minimum required to protect the interest of domestic industry, is recommended to be imposed on imports of Acetylene Black falling under heading 2803.00 of the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975 (28030001 of the ITC).

## 6. Further Procedure

- i)The information provided by various parties may be subjected to verification where necessary, for which they will be informed separately.
- ii) A Public Hearing will be held in due course before making a final determination, for which the date will be informed separately.
- iii)Interested parties may make their views known on these preliminary findings to the undersigned by 9 March 1998.

[F. No. SG/INV/1/97] R. K. GUPTA, Director Genl. (Safeguards)